भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2422

उत्तर देने की तारीख 13दिसंबर, 2021

सोमवार, 22 अग्रहायण,1943 (शक)

क्षेत्र कौशल परिषद

2422 श्री मछीला गुरुमूर्ति: श्री तालारी रंगैय्या:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की योजना सभी पारंपरिक कौशलों को शामिल करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों की संख्या बढ़ाने की है ताकि सभी कारीगर/बुनकर/किसान आदि अपने कौशल को और बेहतर कर सकें और स्थायी आजीविका अर्जित कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित और नियोजित/स्व-रोजगार में लगे पारंपरिक श्रमिकों का डेटाबेस रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में अब तक 37 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया है जो अपने संबंधित क्षेत्रों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं। पुनश्च अधिक क्षेत्र कौशल परिषदों की स्थापना विभिन्न मानदंडों पर आधारित होता है जैसे एसएससी की स्थापना के लिए उद्योग से समर्थन, एसएससी के कार्यकलापों में सहभागिता के लिए उद्योग की रुचि, क्षेत्र का वर्तमान कार्यबल,कौशल उन्नयन/पुन: कौशलीकरण अगले 5-10 वर्षों में अतिरिक्त नए कार्यबल का नियोजन आदि। एसएससी को उस दशा में भी अनुमोदित किया जा सकता है, यदि लक्षित क्षेत्र विशेष हो और असंगठित हो किंतु बड़ा हो और नियोजन के बेहतर अवसरों के लिए कौशलीकरण की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, दिव्यांगजन के लिए कौशल परिषद, घरेलू कामगार कौशल परिषद आदि 7 एसएससी अन्य बातों क साथ-साथ कारीगरों/बुनकरों/कृषकों के लिए काम कर रहे हैं।

(ख) जी हाँ, 2016-17 से प्रशिक्षित और नियोजित/स्व-नियोजित श्रमिकों का क्षेत्र-वार ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रशिक्षित	नियोजित रिपोर्ट
1	कृषि	768846	44467
2	खाद्य प्रसंस्करण	170328	7679
3	फर्नीचर फिटिंग	168204	5640
4	रत्न और आभूषण	117658	10425
5	हस्तशिल्प और कालीन	254786	4910
6	चमड़ा	173510	7414
7	कपड़ा और हथकरघा	252264	9687

****